

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1449] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 24, 2019/वैशाख 4, 1941 No. 1449] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 24, 2019/VAISAKHA 4, 1941

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2019

का.आ. 1633(अ).—केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि नाभिकीय ईंधन और संघटक, भारी पानी और संबद्ध रसायन तथा आणविक ऊर्जा का विनिर्माण या उत्पादन करने वाले औद्योगिक स्थापनों की सेवाओं को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची के मद 28 के अंतर्गत आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा घोषित किया जाना चाहिए।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त उद्योग को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए लोक उपयोगिता सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/3/1997-आई.आर.(पीएल)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2019

S.O. 1633(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services engaged in the industrial establishments manufacturing or producing Nuclear Fuel and components, Heavy Water and Allied Chemicals and Atomic Energy, which is covered by item 28 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares from the date of publication of this notification that the said industry to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act for a period of six months.

[F. No. S-11017 / 3 / 1997-IR(PL)] KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.